उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 संख्या **\$2.2** / 2017 / 9(120) / XXVII(8) / 2017 देहरादूनःः दिनांकःः **2.9** जून, 2017

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 11 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के क्रम में रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति को, ऐसे पूर्तिकार द्वारा, जो रिजस्ट्रीकृत नहीं है, माल या सेवाओं या दोनों की, राज्य के भीतर पूर्ति को उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय राज्य कर से छूट प्रदत्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं;

परन्तु उक्त छूट वहां लागू नहीं होगी, जहां रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का समग्र मूल्य, ऐसे किसी या सभी पूर्तिकारों से, जो रिजस्ट्रीकृत नहीं है या नहीं हैं. एक दिन में पांच हजार रूपये से अधिक है।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

(राधा रतूड़ी) प्रमुख सचिव

सं<u>0 \$22/2017/9(120)/XXVII(8)/2017</u>तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2— निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी / अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित की इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100—100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग—8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3- भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 4- अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 5— एन०आई०सी०
- 6- गार्ड फाईल हेतु।

. W

(हीरा सिंह बसेड़ा) अनुसचिव In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.522/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 29 June, 2017 for general information

Government of Uttarakhand Finance Section-8 No.522/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 Dehradun:: Dated:: 29 June, 2017

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor, in the continuation of the recommendations of the Council is pleased to allow to exempt intra-State supplies of goods or services or both received by a registered person from any supplier, who is not registered, from the whole of the State tax leviable thereon under sub-section (4) of section 9 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017):

Provided that the said exemption shall not be applicable where the aggregate value of such supplies of goods or service or both received by a registered person from any or all the suppliers, who is or are not registered, exceeds five thousand rupees in a day.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

(Radha Raturi) Principal Secretary